सत्यमेव जयते

श्री बंडारू दत्तात्रेय

राज्यपाल, हरियाणा

द्वारा

हरियाणा विधान सभा अधिवेशन

के अवसर पर

मंगलवार, 20 फरवरी, 2024

को दिया गया

अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय तथा सम्मानित सभासदो!

1. हरियाणा की 14वीं विधानसभा के पांचवें बजट सत्र में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। मैं कामना करता हूँ कि सभी प्रदेशवासी स्वस्थ हों, खुशहाल हों, स्वावलम्बी हों और प्रदेश के विकास में हर व्यक्ति की समान रूप से सहभागिता हो।

2. मेरी कामना है कि हरियाणा प्रगति के पथ पर निरंतर गतिशील रहे, विकास के मामले में नित नए आयाम स्थापित करे। यह सम्मानित सदन लगभग 2 करोड़ 85 लाख प्रदेशवासियों की आशाओं का ध्वजवाहक है। अतः आप सबके कंधों पर उन जन आकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी महान लोकतांत्रिक परम्पराएं इस सदन में होने वाली परिचर्चाओं में हमारा मार्गदर्शन करेंगी।

3. माननीय सभासदो! गत वर्ष राष्ट्र को कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करने का गौरव प्राप्त हुआ। हमारे वैज्ञानिकों ने चन्द्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चन्द्रयान–3 की सफल लैंडिंग करवाकर भारतवर्ष का परचम लहराने का काम किया। इसी प्रकार, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भेजा गया आदित्य एल–1 भी अन्तरिक्ष में अपनी आभा बिखेरता रहेगा। गत वर्ष भारत को जी–20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत कई गम्भीर मुद्दों पर अन्तर्राष्ट्रीय सहमति कायम करवाने में सफल रहा और विश्व ने हमारी नेतृत्व क्षमता का लोहा माना है।

4. अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा से आज समूचा देश राममय है। राष्ट्र के कण कण में भक्ति, शक्ति, गर्व और गौरव का भाव व्याप्त है। इस पवित्र पराकाष्ठा के लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। लगभग 500 वर्षों की लम्बी प्रतीक्षा के पश्चात्, देशवासियों को यह दिन दिखाने के निमित्त बने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को भी मैं दिल की अथाह गहराइयों से साधुवाद देता हूँ। भगवान श्रीराम के मंदिर निर्माण के स्वप्न को वास्तविकता बनाकर उन्होंने करोड़ों भारतीयों की आशाओं को पूरा किया है तथा उनकी आस्था को सम्बल प्रदान किया है। यह मन्दिर हमारे राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत का अप्रतिम प्रतीक है।

5. माननीय सभासदो! हरियाणा के कण कण में वीरों की कुर्बानियां समाई हुई हैं। हमारे बहादुर जवान देश की सीमाओं पर हर क्षण चौकस हैं। हमारे किसानों के परिश्रम से देश के अन्न भंडार भर जाते हैं। हमारे खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में जीतकर देश का मान बढ़ाते हैं। हरियाणा सही मायने में 'जय जवान जय किसान जय विज्ञान' के नारे को चरितार्थ करता है।

6. प्रति व्यक्ति आय की बात हो, उद्योगों के विकास की बात हो, सामाजिक सुरक्षा और जनकल्याण की डगर हो या फिर कृषि में नवाचार की पहल, आज हर मामले में राष्ट्रीय फलक पर हरियाणा की बलिष्ठ उपस्थिति नज़र आती है। हमारा कृषि प्रधान प्रदेश आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के रथ पर सवार होकर पूरे वेग से प्रगति पथ पर अग्रसर है।

7. मेरी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सेवा और सुशासन को आधार बनाकर प्रदेश के सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लिए दिन प्रतिदिन कार्यरत है। मेरी सरकार गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के कल्याण–उत्थान को निरंतर सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का 'अन्त्योदय' का दर्शन व्यवस्था परिवर्तन और सुशासन के पथ पर एक प्रकाश स्तम्भ के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहा है।

व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन

8. माननीय सभासदो! 'सुशासन से सेवा' ही मेरी सरकार का संकल्प है। वर्ष 2021 को 'सुशासन संकल्प वर्ष' और 2022 को 'सुशासन परिणाम वर्ष' के रूप में मनाया गया। सुशासन का लक्ष्य अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान होता है, इसलिए वर्ष 2023 को 'अन्त्योदय उत्थान वर्ष' के रूप में मनाया गया। इस वर्ष को मेरी सरकार 'संकल्प से परिणाम वर्ष' के रूप में मना रही है। 'अन्त्योदय' के लक्ष्य को प्राप्त करने के मनोरथ से, मेरी सरकार ने प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को न्यूनतम करने के लिए बड़े पैमाने पर ई–शासन का प्रयोग किया है। सरकार ने टैक्नॉलोजी का उपयोग आमजन के हित में करते हुए एक कुशल चित्रकार के समान सुशासन रूपी तूलिका से हरियाणा की तस्वीर और आमजन की तकदीर को संवारने का काम किया है।

9. मेरे विचार से सुशासन का सीधा सा अर्थ है–आमजनों के रोज़मर्रा के जीवन को सरल बनाना। आम आदमी को सरकार की सेवाओं तथा कार्यक्रमों का लाभ घर बैठे आसानी से और समय पर मिल जाए, अपने

हक के लिए उसे सरकारी कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें, किसी के आगे गिड़गिड़ाना न पड़े, यही सुशासन है। प्रदेश के आमजन के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने 'जन संवाद' कार्यक्रम शुरू किया है। जन संवाद के दौरान प्राप्त मांगों व शिकायतों के समाधान के लिए जन संवाद पोर्टल बनाया है।

10. माननीय सभासदो! माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 नवम्बर, 2023 को आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र झारखंड के खूँटी से 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' का शुभारंभ किया था। समावेशी विकास के दृष्टिकोण पर आधारित इस यात्रा का एक प्रमुख उद्देश्य केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों की कल्याणकारी नीतियों के बारे में जागरुकता पैदा करना और उनकी शतप्रतिशत परिपूर्णता सुनिश्चित करना था। हरियाणा में अब तक इस यात्रा के दौरान 6225 ग्राम पंचायतों और 578 शहरी स्थानीय निकायों में 6803 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें लाखों लोगों ने भाग लिया।

11. मेरी सरकार ने व्यक्तिपरक पहचान पत्र 'आधार' से आगे जाकर 'परिवार पहचान पत्र' के रूप में पूरे परिवार की पहचान की व्यवस्था की और इसे सरकारी योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचाने का माध्यम बनाया। परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अब तक लगभग 71.42 लाख परिवारों के 2.85 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण हो चुका है।

12. मेरी सरकार ने प्रदेश में विभिन्न योजनाओं का लाभार्थी तक सीधा लाभ सुनिश्चित करते हुए डी.बी.टी. पोर्टल के माध्यम से अब तक

74679.57 करोड़ रुपये भेजे हैं। इसके माध्यम से 36.75 लाख फर्जी अथवा छद्म लाभार्थियों को हटाया गया है, जिससे 1182.23 करोड़ रुपये वार्षिक की बचत होती है।

13. सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली विभिन्न सेवाएं और सूचनाएं अब मोबाइल फोन पर एक ही ऐप के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा 'जन सहायक हैल्प मी ऐप' शुरू किया गया है। इस ऐप के माध्यम से नागरिक अपने सुझाव भी राज्य सरकार को दे सकते हैं।

14. मेरी सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जोरदार मुहिम चलाई है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा वर्ष 2023 में 205 मामले दर्ज किए गए, 152 छापेमारी की गई और 186 सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 30 राजपत्रित अधिकारी, 156 गैर–राजपत्रित अधिकारी और 40 निजी व्यक्ति शामिल हैं।

अन्त्योदय की वचनबद्धता

15. मेरी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के समानता, समरसता व सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का अनुकरण करते हुए अंत्योदय के लिए कटिबद्ध है। इनमें 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' प्रमुख है, जिसका उद्देश्य 1.80 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा वाले सबसे गरीब परिवारों का उत्थान करना है। मेरी सरकार बुजुर्गों, विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, किन्नरों, विधुरों, अविवाहित पुरुषों और महिलाओं, तीसरे और चौथे चरण के कैंसर रोगियों, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ितों, निराश्रित बच्चों, केवल लड़कियों के माता–पिता, स्कूल न जाने

वाले दिव्यांग बच्चों और कश्मीरी विस्थापितों समेत समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों को सम्मान भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाकर 3000 रुपये मासिक की गई है।

16. मेरी सरकार ने 1 लाख 80 हजार रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान भारत–'चिरायु' योजना शुरू की है। इस योजना में शामिल किए जाने वाले परिवारों का 5 लाख रुपये वार्षिक तक उपचार का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। एक करोड़ 11 लाख आयुष्मान चिरायु कार्ड बनाए गए हैं और 9.64 लाख मरीजों के इलाज के लिए 1,247 करोड़ रुपये के क्लेम दिये गए हैं। केवल 1500 रुपये के वार्षिक अंशदान पर 3 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन पर प्रति परिवार प्रति वर्ष लगभग 3393 रुपये का खर्च वहन किया जा रहा है। अन्त्योदय परिवारों की स्वास्थ्य जांच के लिए शुरू की गई 'निरोगी हरियाणा' योजना के तहत गरीब व वंचित परिवारों के 47.93 लाख व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जांच की गई है और 2 करोड़ 54 लाख निःशुल्क टैस्ट किये गये हैं।

17. सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की मकान संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 'हाउसिंग फार ऑल' विभाग गठित किया गया है तथा मेरी सरकार ने 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' पोर्टल भी शुरू किया है। इस पोर्टल पर अब तक 2,90,000 गरीब परिवारों ने पंजीकरण करवाया है। प्रारम्भिक चरण में प्रदेश के 14 शहरों के लिए प्लॉट की बुकिंग के लिए पोर्टल पर 1 फरवरी, 2024 से आवेदन मांगे गए हैं। गत 14 फरवरी तक 9514 लोगों ने पंजीकरण किया है।

18. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों को 80,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना के तहत वर्ष 2022–23 के दौरान 11,700 से अधिक लाभार्थियों को लगभग 95 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि दी गई है।

19. मेरी सरकार ने 'प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान धन योजना' के तहत खुदरा विक्रेताओं और दुकानदारों के लिए मासिक पेंशन सुनिश्चित की है। 'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' के तहत 1,32,000 से अधिक रेहड़ी फड़ी वालों को 10 हजार रुपये तक का ब्याज रहित ऋण दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टरों में रेहड़ी फड़ी के लिए मार्किट बनाई जा रही है। पंचकूला से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। व्यापारियों के लिए 'मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना' और 'मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना' शुरू की है। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है।

20. 'प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के तहत प्रदेश में 44 लाख 87 हजार परिवारों को गेहूं और बाजरा मुफ्त दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 'अंत्योदय आहार योजना' के तहत सभी ए.ए.वाई. और बी.पी.एल. परिवारों को सरसों/सूरजमुखी का 2 लीटर तेल और एक किलोग्राम चीनी भी दी जाती है। 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' के तहत गरीब परिवारों को 12.05 लाख मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं।

21. मेरी सरकार अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक व शैक्षणिक उत्थान के लिए प्रयासरत है। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के लिए उच्च पदों पर भी पदोन्नति के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रुप–ए और बी पदों पर पदोन्नति में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक काम किया है। गरीब को अपनी बेटी के हाथ पीले करने में आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े, इसके लिए 'मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना' में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जातियों, विमुक्त जनजातियों और टपरीवास जातियों के परिवारों के लिए शगुन राशि 51 हजार रुपये से बढ़ाकर 71 हजार रुपये की गई है। गत चार वर्षों में अब तक 1,15,518 लड़कियों के विवाह पर 472.51 करोड़ रुपये की राशि दी गई।

22. अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्न उच्च प्रतियोगी तथा प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुफ्त कोचिंग दिलवाई जाती है। इस स्कीम के अन्तर्गत आय सीमा 2.50 लाख रुपये वार्षिक निर्धारित की गई है। अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों के मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए डॉ. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना के तहत वार्षिक पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4.00 लाख रुपये की गई है। सभी वर्गों के छात्र–छात्राओं को इस योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के तहत प्रतिवर्ष 8,000 रुपये से 12,000 रुपये तक छात्रवृत्ति दी जाती है।

23. माननीय सभासदो! मेरी सरकार श्रमिकों के कल्याण व उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। राज्य सरकार द्वारा अकुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन प्रत्येक छः माह में बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा भवन

एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को बेटे की शादी में दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 21,000 रुपये की गई है, जबकि बेटी की शादी के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाकर 50,000 रुपये की गई है तथा कन्यादान के रूप में 51,000 रुपये यानी कुल 1,01,000 रुपये की राशि दी जाती है।

24. बोर्ड में पंजीकृत श्रमिकों के मेधावी बच्चों को दसवीं तथा 12वीं कक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता के आधार पर 21,000 रुपये से 51,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। श्रमिकों के बच्चों की सरकारी तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई का पूरा खर्च बोर्ड द्वारा वहन किया जाता है। बोर्ड द्वारा निजी तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई का खर्च सरकारी संस्थानों में लगने वाले खर्च के समान वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त, पंजीकृत श्रमिकों के तकनीकी व व्यावसायिक संस्थानों में पढ़ने वाले बच्चों के हॉस्टल का एक लाख 20 हजार रुपये तक सालाना खर्च भी बोर्ड द्वारा वहन किया जा रहा है। 'मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना' के तहत दिए जाने वाले पुरस्कारों की राशि न्यूनतम 21 हजार रुपये से बढ़ाकर 51 हजार रुपये और अधिकतम एक लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक की गई है।

किसान कल्याण

25. माननीय सभासदो! मेरी सरकार किसानों द्वारा बहाए गए पसीने की एक–एक बूँद की कीमत बखूबी समझती है तथा उनके कल्याण के लिए अनवरत प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के 19.94 लाख किसानों के खातों में गत चार वर्षों में

4157.73 करोड़ रुपये की राशि सीधे जमा करवाई गई है। साथ ही, राज्य सरकार ने 14 फसलों की एम.एस.पी. पर खरीद करके एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के खातों में पिछले 7 सीजन में खरीदी गई फसल की एवज में लगभग 90 हजार करोड़ रुपये की राशि सीधे डाली गई। भावांतर भरपाई योजना के अन्तर्गत बाजरा उत्पादक किसानों के बैंक खातों में 836.12 करोड़ रुपये की राशि डाली गई है।

26. मेरी सरकार प्राकृतिक आपदाओं में ढाल बनकर किसान के साथ खड़ी रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत 32.06 लाख किसानों को उनकी फसल खराब होने पर लगभग 8,178 करोड़ रुपये के क्लेम दिये गये हैं। प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर मुआवजा राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गई है। गत चार वर्षों में प्राकृतिक आपदा से फसलें खराब होने पर किसानों को लगभग 1845.95 करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के रूप में दी गई।

27. किसान को राहत देने के लिए भावांतर भरपाई योजना शुरू की है। मृदा स्वास्थ्य को गिरावट से बचाने और खतरनाक कीटनाशकों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए मेरी सरकार ने प्राकृतिक खेती योजना लागू की है। इसके लिए शुरू किए गए समर्पित प्राकृतिक खेती पोर्टल पर अब तक 13,388 किसानों ने अपना पंजीकरण किया है। कुरुक्षेत्र गुरुकुल, जिला करनाल के घरौंडा, जीन्द के हमेटी तथा सिरसा के मंगियाना में 4 प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र खोले गये हैं।

28. 'मेरा पानी–मेरी विरासत' योजना के तहत 1 लाख 72 हजार एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें बोने पर 7,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से लगभग 117.22 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है। समय पर ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को बिना ब्याज फसली ऋण की सुविधा दी गई है। प्रदेश में 12 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कुछ में इजराइल की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है।

29. नई व अतिरिक्त मंडियों के विकास पर 1095 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इसके अलावा, 100 करोड़ रुपये की लागत से नई तथा अतिरिक्त अनाज व सब्जी मंडियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। गन्नौर में 3050 करोड़ रुपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉर्टिकल्चर मार्केट तथा पिंजौर में 78 एकड़ भूमि पर 150 करोड़ रुपये की लागत से सेब, फल एवं सब्जी मण्डी निर्माणाधीन है। राज्य की 108 मंडियों को 'राष्ट्रीय कृषि बाजार पोर्टल' (ई–नाम) से जोड़ा गया है। 'अटल किसान मजदूर कैंटीन' योजना के तहत 10 रुपये प्रति थाली की रियायती दर से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए 25 मण्डियों में कैंटीन शुरू की गई हैं। 15 और मंडियों में भी ऐसी कैंटीन जल्द शुरू की जाएंगी।

30. माननीय सभासदो! पशुपालन हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। मेरी सरकार किसानों को आय के अतिरिक्त साधन मुहैया करवाने के लिए पशुपालन को प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश में 20 व 50 दुधारू पशुओं की डेयरी स्थापित करने पर लाभार्थियों को बैंक ऋण पर ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। साथ ही, 2, 4 तथा 10 दुधारू

पशुओं की डेयरी इकाइयां स्थापित करने पर लाभार्थियों को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। सांझी डेयरी योजना को पायलट आधार पर जिला अम्बाला, रोहतक, जींद, कुरुक्षेत्र और सिरसा के पांच गांवों में लागू किया जा रहा है।

31. देसी गायों के प्रोत्साहन हेतु हरयाना, साहीवाल और बेलाही नस्ल की अधिक दूध देने वाली गाय के पालकों को 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना' भी चलाई जा रही है। अनुसूचित जाति से सम्बन्धित लाभार्थियों के पशुओं का बीमा मुफ्त किया जाता है। इसके अलावा, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा 'मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना' के अन्तर्गत 30,747 लाभार्थियों को अब तक 72.12 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है।

32. पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1 लाख 50 हजार पशुपालकों को कार्ड दिए जा चुके हैं। दुर्घटना बीमा योजना के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 10 लाख रुपये प्रतिव्यक्ति दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। मेरी सरकार ने पशुपालकों को उनके द्वार पर पशुचिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से मोबाइल पशु चिकित्सा की अनूठी पहल की है। पूर्ण रूप से निर्मित 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की खरीद की जा चुकी है।

33. माननीय सभासदो! मेरी सरकार ने पिराई सीजन 2023–24 हेतु गन्ने की अगेती किस्मों के लिए राज्य परामर्शी मूल्य 386 रुपये प्रति

क्विंटल और पछेती किस्मों के लिए 379 रुपये प्रति क्विंटल का भाव दिया है। सरकार ने आगामी पिराई सीजन 2024–25 के लिए भी अगेती और पछेती किस्मों के लिए क्रमशः 400 तथा 393 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देने का निर्णय लिया है। ग्रीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाते हुए, मेरी सरकार ने कैथल और जींद, रोहतक और महम, करनाल और असंध, गोहाना और सोनीपत तथा पलवल सहकारी चीनी मिलों में कलस्टर आधार पर इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।

34. माननीय सभासदो! मेरी सरकार पानी की एक–एक बूंद का इष्टतम उपयोग करने तथा वितरण में होने वाली पानी की बर्बादी को कम करने के लिए, नहरों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है।

35. 'हर खेत को पानी' मुहैया करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2023–24 के दौरान रीमॉडलिंग और पुनर्वास की 72 परियोजनाएं पूरी की गई हैं। इनमें जे.एल.एन. फीडर तथा हांसी शाखा की प्रमुख परियोजनाएं भी शामिल हैं। डार्क जोन में खेतों में एकत्रित हुए बारिश के पानी से भू–जल पुनर्भरण के लिए 893 रिचार्ज वैल का निर्माण किया गया है। वर्ष 2023–24 के दौरान जिला महेंद्रगढ़ में 5 चेक डैम और 26 जलाशयों का निर्माण कर लगभग 250 करोड़ लीटर पानी संरक्षित किया गया है।

36. सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई एवं कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। तालाबों के जीर्णोद्धार एवं कायाकल्प के साथ–साथ गन्दे पानी के उपचार एवं प्रबंधन के उद्देश्य से हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण का

गठन किया गया है। अमृत सरोवर मिशन के तहत 1689 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य पूरा हो चुका है।

37. राज्य सरकार यमुना तथा उसकी सहायक नदियों–गिरि और टोंस से राज्य को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना नदी के ऊपरी हिस्से पर रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ व्यासी बांधों के निर्माण के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। इन बांधों के पूरा होने पर हरियाणा को कुल भंडारित पानी का 47.81 प्रतिशत पानी मिलेगा।

38. राज्य सरकार ने सरस्वती नदी में प्रवाह के लिए सरस्वती नदी पुनरुद्धार तथा धरोहर विकास परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 388.16 करोड़ रुपये लागत की एक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की है। आदिबद्री बांध के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हो गया है। यह बांध हिमाचल सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, जिसके जून, 2026 तक पूरा होने की सम्भावना है।

39. मेरी सरकार रावी–ब्यास नदियों के पानी का अपना वैध हिस्सा प्राप्त करने और सतलुज–यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले में निरंतर ठोस पैरवी की जा रही है।

शिक्षित, सक्षम, स्वावलम्बी युवा

40. माननीय सभासदो! मेरी सरकार अपने युवाओं में निहित अपार क्षमता को बखूबी पहचानती है। इस क्षमता का दोहन करने के लिए, सरकार रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजित करने को प्राथमिकता दे रही है। मेरी सरकार ने पारदर्शिता एवं मैरिट के आधार पर गत चार वर्षों के दौरान 42,735 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके अलावा,

ग्रुप–सी और डी के 60,000 से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने के लिए ग्रुप–सी व डी की भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त किया है। युवाओं को बार–बार प्रतियोगी परीक्षा से मुक्ति दिलाने के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा शुरू की गई है।

41. राज्य सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा समाप्त की है। निगम द्वारा पहले से कार्यरत एक लाख 8 हजार से अधिक अनुबंधकर्मियों को रोल पर लिया गया है। इसके अलावा, 13,133 नए कर्मी अनुबंध पर लिए गए हैं। अब यह निगम प्राइवेट सेक्टर के साथ–साथ विदेशों में भी युवाओं की प्लेसमेंट के अवसर तलाश रहा है।

42. मेरी सरकार ने अब तक 4080 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन किया है और 1,17,500 से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार सहायता प्रदान की गई है।

43. माननीय सभासदो! केन्द्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति–2020 को वर्ष 2050 तक लागू करने का लक्ष्य रखा गया है परन्तु मेरी सरकार इसे वर्ष 2030 तक ही लागू करने को संकल्पबद्ध है। इस नीति को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं का बेहतरीन बुनियादी ढांचा विद्यमान है। यह हर्ष का विषय है कि आज प्रदेश में कुल 182 राजकीय महाविद्यालय हैं।

44. गरीब परिवारों के बच्चों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने के समान अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से 1 लाख 80 हजार रुपये की वार्षिक आय वाले परिवारों के पात्र विद्यार्थियों को चिराग योजना के तहत

दूसरी से 12वीं कक्षा तक निजी स्कूलों में दाखिला दिलवाया जाता है। सरकार द्वारा गरीब परिवारों के विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त पुस्तकें, वर्दी व लेखन सामग्री दी जाती है।

45. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के तहत 1185 विद्यालयों में छठी से 8वीं कक्षा तक प्री वोकेशनल एजुकेशन शुरू की गई है। राज्य में सी.बी.एस.ई. से सम्बद्ध 146 नए राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं। पीएम श्री स्कूल योजना के अंतर्गत राज्य में 124 स्कूल खोले गए हैं। प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापरक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए 1,420 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं।

46. राज्य सरकार ने ई–अधिगम योजना के तहत सरकारी स्कूलों के 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों तथा उन्हें पढ़ाने वाले अध्यापकों को 2 जी.बी. डेटा के साथ 5.50 लाख टैबलेट्स मुफ्त दिए हैं।

47. पी.एम.–ऊषा योजना के तहत महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक और भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय, खानपुर कलां (सोनीपत) को सुदृढ़ करने के लिए 20–20 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। जे.सी. बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फरीदाबाद, दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मुरथल और गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हिसार में हिंदी में बी.टेक. पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं।

48. जिला पलवल के दुधौला में स्थापित श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय ने सत्र 2023–24 में व्यावसायिक, स्नातक और स्नातकोत्तर

कार्यक्रम चलाने के लिए प्रदेश के 24 कॉलेजों को संबद्ध किया है। युवाओं को आर्थिक तथा चहुंमुखी विकास में भागीदार व सक्षम बनाने के उद्देश्य से गठित 'हरियाणा कौशल विकास मिशन' द्वारा 31,374 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। गत चार वर्षों में 15 नए राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों की स्थापना की गई, जिससे विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता में 3278 की वृद्धि हुई है।

49. सुपर–100 कार्यक्रम के तहत सरकारी स्कूलों के मेधावी विद्यार्थियों को आई.आई.टी., जे.ई.ई. और एन.ई.ई.टी. जैसी परीक्षाओं के लिए रेवाड़ी, पंचकूला, करनाल व हिसार में विशेष कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। अब तक 379 विद्यार्थियों ने जे.ई.ई. एडवांस, एन.ई.ई.टी. और आई.आई.टी. एडवांस की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए सुपर–100 कार्यक्रम की तर्ज पर सुपर एन.डी.ए. कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इसमें विशेषज्ञ संस्थाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 100 विद्यार्थियों को एन.डी.ए. तथा एस.एस.बी. परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है।

युवा

50. माननीय सभासदो! हमारे युवाओं की खेलों में उपलब्धियां देखकर सीना गर्व से फूल जाता है। हमारे खिलाड़ियों ने ओलम्पिक व अन्य अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। वर्ष 2022 में बर्मिंघम में हुए कॉमनवैल्थ गेम्स में भारत को मिले 61 पदकों में से 20 पदक हमारे खिलाड़ियों ने जीते।

51. मुझे इस सम्मानित सदन को यह बताते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है कि हरियाणा अपने पदक विजेता खिलाड़ियों को सर्वाधिक नकद पुरस्कार राशि देने वाले राज्यों में से एक है। मेरी सरकार ने खिलाड़ियों को गत चार वर्षों में 224.20 करोड़ रुपये से अधिक के नकद पुरस्कार दिए हैं। हरियाणा देश का पहला राज्य है, जिसने ओलम्पिक व पैरालम्पिक खेलों के लिए क्वालीफाई करते ही खिलाड़ी को तैयारी के लिए 5 लाख रुपये की एडवांस राशि देने की व्यवस्था की है। इसके साथ ही एशियन, पैरा एशियन, कॉमनवैल्थ खिलाड़ियों को भी 2.50 लाख रुपये एडवांस देने का प्रावधान किया है।

52. चालू वित्त वर्ष में प्रदेश में 1100 खेल नर्सरियां आवंटित की गईं। 24 आवासीय अकादमियों में खिलाड़ियों को प्रतिदिन 400 रुपये डाइट मनी दी जाती है। राज्य सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 550 नए पद सृजित किए हैं। खिलाड़ियों को ग्रुप–सी में 3 प्रतिशत और डी की नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण

53. माननीय सभासदो! नारी का दूसरा नाम शक्ति है। सामाजिक जीवन में ऐसा कोई काम नहीं, जो उनके लिए असम्भव हो। ज्ञान–विज्ञान से लेकर शिक्षा तक, राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, चिकित्सा से लेकर समाज सेवा तक, आज महिलाएं अपनी मेहनत और मेधा के दम पर हर क्षेत्र में इतिहास रच रही हैं। मेरी सरकार ने महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और उनके सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण को सर्वोपरि रखा है।

54. एक समय था, जब लिंगानुपात के मामले में हरियाणा की स्थिति अच्छी नहीं थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वर्ष 2015 में पानीपत से 'बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम की शुरुआत कर बेटियों को बचाने और बेटियों को पढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता जाहिर की। सरकार के ठोस प्रयासों से आज हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात की दर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। डायल–112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली के तहत पुलिस एमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल का औसत रिस्पॉन्स टाइम 7 मिनट 37 सैकंड हो गया है। डायल–112 के माध्यम से 'ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस' शुरू की गई है। यात्रा के दौरान असुरक्षित महसूस करने वाली कोई भी महिला डायल–112 के माध्यम से अपनी यात्रा की निगरानी करवा सकती है।

55. 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' के तहत गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषाहार के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाने की बात हो, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का सवाल हो, 'मुख्यमंत्री दूध उपहार' योजना के तहत बच्चों, गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं को फोर्टिफाइड दूध उपलब्ध करवाने का विषय हो, 'महिला एवं किशोरी सम्मान योजना' के तहत बी.पी.एल. परिवारों की किशोरियों व महिलाओं को मुफ्त सेनेटरी पैड उपलब्ध करवाने की बात हो या फिर बीमारियों से बचाव के लिए 'मिशन इन्द्रधनुष' के जरिये गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का विषय, मेरी सरकार ने हर प्रकार से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखा है।

56. मेरी सरकार हरियाणा में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करने के लिए प्रयासरत है। पंचायती

राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देकर ग्रामीण विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है। उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन करके और इन्हें 'हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका' मिशन से वित्तीय सहायता दिलवाकर सरकार ने महिलाओं के संकल्प को सम्बल प्रदान किया है।

57. मेरी सरकार ने 51 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया है तथा 151 वीटा बिक्री केन्द्रों का संचालन महिलाओं के हाथों में दिया है। मेरी सरकार ने निर्णय किया है कि भविष्य में अलॉट होने वाले राशन डिपो में से 33 प्रतिशत महिलाओं को दिए जाएंगे।

58. कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं की परेशानी को दूर करने के उद्देश्य से विस्तृत क्रेच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। क्रेच में बच्चों के खेलने के सामान के साथ ही पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जाँच और टीकाकरण, सोने की व्यवस्था, शिक्षा तथा शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास के लिये भी प्रबंध किए जाएंगे।

उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं

59. माननीय सभासदो! मेरी सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए एलोपैथी के साथ–साथ प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों को भी बढ़ावा दे रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का हमारा संकल्प पूरा हो गया है। इस समय प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज कार्यात्मक हैं और 11 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का

कार्य प्रगति पर है। जिला करनाल के कुटैल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है।

60. सिविल अस्पताल, अम्बाला छावनी में अटल कैंसर देखभाल केंद्र शुरू हो गया है। यह प्रदेश का पहला सरकारी कैंसर चिकित्सा केन्द्र है, जिसमें अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत लोगों को सी.टी. स्कैन, एम.आर.आई., हैमोडायलिसिस और कैथ लैब की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा, सभी जिलों में पी.पी.पी. सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है।

61. रेवाड़ी में प्रदेश के पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का शिलान्यास गत 16 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कर कमलों से सम्पन्न हुआ है।

62. कुरुक्षेत्र में स्थापित देश के पहले श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय में 14 विषयों में 82 सीटों पर आयुर्वेद में एम.डी. पाठ्यक्रम शुरू हो चुका है। पंचकूला में लगभग 270.54 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे 250 बिस्तर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में ओ.पी.डी. शुरू हो चुकी है। इसमें 100 आयुर्वेद बिस्तर और 150 प्राकृतिक चिकित्सा बिस्तर होंगे।

मजबूत बुनियादी ढांचा

63. माननीय सभासदो! विकसित हरियाणा के स्वप्न को साकार करने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा पहली आवश्यकता है। यह लोगों के जीवन को तो सरल बनाता ही है, उद्योग और निवेश को आकर्षित कर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देता है। आज प्रदेश में 4 लेन और 6 लेन के हाइवे का जाल बिछाया गया है, यातायात को सुगम बनाने के

लिए जगह–जगह फ्लाईओवर और अंडरब्रिज बने हैं, मेट्रो का विस्तार हुआ है, नई रेल लाइनें बिछी हैं, राज्य ने एयर कनेक्टिविटी की दिशा में भी कदम बढ़ाए हैं।

64. अब हरियाणा का प्रत्येक जिला राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ गया है। प्रदेश में 19,920 करोड़ रुपये की लागत से 32,915 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया गया। इसके अलावा, 2322.43 करोड़ रुपये की लागत से 2123 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया है।

65. गत चार वर्षों के दौरान 728 करोड़ रुपये की लागत से 36 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा 1503 करोड़ रुपये की लागत से 52 रेलवे ऊपरगामी व भूमिगत पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–III के तहत 1026 करोड़ रुपये की लागत से 2349 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और 119 किलोमीटर लम्बी सड़कों का कार्य प्रगति पर है। इस अवधि के दौरान यातायात को सुगम बनाने के लिए 13 टोल टैक्स बैरियर हटाये गये हैं।

66. मेरी सरकार बढ़ते माल और यात्री यातायात की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य में सड़क के साथ–साथ रेलवे बुनियादी ढांचे को भी निरंतर उन्नत कर रही है। रोहतक–महम–हांसी रेलवे लाइन पर रेल सेवा शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गत 16 फरवरी को ही 470 करोड़ रुपये की लागत से भिवानी–डोभ भाली रेलवे लाइन, 410 करोड़ रुपये की लागत से मानहेरू–बवानी खेड़ा रेलवे लाइन, 350 करोड़ रुपये की लागत से रेवाड़ी–काठूवास रेलवे लाइन तथा

310 करोड़ रुपये की लागत से काठूवास–नारनौल रेलवे लाइन दोहरीकरण परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया किया गया है। इन लाइनों के दोहरीकरण से कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यातायात व माल ढुलाई सुगम होगी।

67. उत्तर रेलवे द्वारा 61 किलोमीटर लम्बी करनाल–यमुनानगर रेलवे लाइन और 30 किलोमीटर लम्बी फर्रुखनगर–झज्जर रेलवे लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कैथल में एलिवेटेड रेलवे स्टेशन और ट्रैक के व्यवहार्यता अध्ययन का कार्य प्रगति पर है। कुरुक्षेत्र शहर में 265.18 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना का कार्य प्रगति पर है। के.एम.पी. एक्सप्रेस–वे के साथ–साथ पलवल के पृथला से सोनीपत तक 5,566 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना पर कार्य शुरू हो चुका है।

68. हरियाणा एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई है। इससे राज्य में विमानन बुनियादी ढांचे के विकास, रोजगार सृजन और विमानन क्षेत्र, उड़ान प्रशिक्षण अकादमियों, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल में कौशल विकास तथा एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण में तेजी आएगी। हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम पर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बनाया गया है। अप्रैल माह से इस एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू होने की सम्भावना है। अम्बाला में 20 एकड़ भूमि पर एक घरेलू एयरपोर्ट बनाया जा रहा है।

69. माननीय सभासदो! मेरी सरकार ने 'जल जीवन मिशन' के अंतर्गत 'हर घर–नल से जल' अभियान के तहत लगभग 13 लाख ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन देने का कार्य किया है। सरकार ने महाग्राम योजना के अन्तर्गत, 2011 की जनगणना के अनुसार 10,000 से अधिक की जनसंख्या वाले गांवों में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तक संवर्धित पेयजल आपूर्ति तथा पर्याप्त सीवरेज उपचार बुनियादी ढांचे के लिए एक सर्व–समावेशी दृष्टिकोण की परिकल्पना की है। अब तक 12 गांवों में सीवरेज का प्रावधान किया जा चुका है तथा 10 और गांवों में 31 मार्च, 2024 तक सीवरेज का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश में गत चार वर्षों में 261 करोड़ रुपये की लागत से 17 मल शोधन संयंत्र शुरू किए गए हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 6060 करोड़ रुपये की लागत से 88 नहर आधारित तथा 1750 नलकूप आधारित जलघर स्थापित किए गए हैं। ट्रीटेड वेस्ट वाटर पॉलिसी के तहत बिजली संयंत्रों, नगर निगमों, उद्योगों और सिंचाई जैसे गैर–पेयजल उपयोग के संभावित क्षेत्रों की पहचान की गई है। इनमें 200 लाख लीटर उपचारित जल प्रतिदिन प्रयोग किया जा रहा है।

70. माननीय सभासदो! मेरी सरकार ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास और प्रदेशवासियों को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, यमुनानगर में 6900 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित की जाने वाली 800 मेगावाट क्षमता की नई यूनिट का कार्य भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सौंपा गया है। यह कार्य 57 महीने में पूरा किया जाएगा। मुझे इस सम्मानित सदन को यह अवगत करवाते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 'म्हारा गांव–जगमग गांव'

योजना के तहत आज तक 5805 गांवों को 24 घंटे बिजली आपूर्ति दी जा रही है। प्रदेश में बिजली ए.टी.सी. लॉस वर्ष 2022–23 में केवल 12.32 प्रतिशत रह गया है। भारत सरकार द्वारा करवाए गए एक सर्वे में राज्य के दोनों बिजली वितरण निगमों को ए+ ग्रेड मिला है।

71. प्रदेश में 1809 करोड़ रुपये की लागत से 28 नए सब–स्टेशनों की स्थापना की गई है, मौजूदा सब–स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए 266 ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं तथा 819 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाइनें बिछाई गई हैं। प्रदेश में 228.09 मेगावाट क्षमता के जमीन आधारित सोलर पवर प्रोजेक्ट स्थापित किये गए हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना के अन्तर्गत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पम्प उपलब्ध करवाए जा रहे है। इस योजना के तहत 67,418 सोलर पंप स्थापित किए जा चुके हैं तथा 70,000 नये सोलर पंप लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। गांवों में स्ट्रीट लाइटों और अमृत सरोवरों पर एल.ई.डी. आधारित सोलर स्ट्रीट लाइट तथा हाईमास्ट लाइटें लगाने की योजना चलाई जा रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 7169 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 2024–25 के दौरान 10,000 और ऐसी लाइटें लगाई जाएंगी।

72. मेरी सरकार ने हरियाणा राज्य परिवहन के बस बेड़े में बसों की संख्या 4500 से बढ़ाकर 5300 की है। मानेसर सहित गुरुग्राम और फरीदाबाद में सम्बन्धित महानगर विकास प्राधिकरणों द्वारा सिटी बस सेवा शुरू की जा चुकी है। सरकार ने 9 अन्य शहरों–पानीपत, पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार और रेवाड़ी में सिटी इलेक्ट्रिक ए.सी. बस सेवा चलाने का निर्णय लिया है, जिनमें से

पानीपत व यमुनानगर में इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जा चुकी है। यह सेवा चरणबद्ध ढंग से जून, 2024 तक अन्य शहरों में भी शुरू की जाएगी। छात्राओं व महिलाओं के लिए 213 मार्गों पर 181 विशेष बस सेवा उपलब्ध करवाई गई है।

सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास

73. माननीय सभासदो! पंचायतों की बागडोर पढ़े–लिखे हाथों में सौंपने के बाद, मेरी सरकार उन्हें कार्य और निधियां हस्तांतरित करके उनके सशक्तिकरण की दिशा में तत्परता से काम कर रही है। अब पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर बड़ी जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व देने के बाद पिछड़ा वर्ग (ए) के व्यक्तियों को भी पंचायती राज संस्थाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं में मतदाताओं को निर्वाचित प्रतिनिधि को हटाने का अधिकार भी दिया गया है। जिला परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पंचायत समिति अध्यक्ष, पंचायत समिति उपाध्यक्ष, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच तथा पंच, सभी का मानदेय बढ़ाया गया है। पूर्व जिला परिषद अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, पूर्व पंचायत समिति अध्यक्षों, उपाध्यक्षों तथा पूर्व सरंपचों को पेंशन दी जा रही है।

74. गांवों में लाल डोरा के अन्दर स्थित सम्पत्तियों पर मालिकाना हक को लेकर काफी विवाद होते थे। मेरी सरकार ने लाल डोरे के भीतर आने वाली सम्पत्तियों के मालिकाना हक दिए हैं। सभी 143 तहसीलों व उप–तहसीलों में हरियाणा भूमि अभिलेख सूचना प्रणाली 'वैब हैलरिस' लागू की गई है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए राज्य की सभी तहसीलों व

उप–तहसीलों में ई–दिशा केन्द्रों के माध्यम से नई रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू की गई है। मेरी सरकार किसान हित में, सरकारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का सहारा न लेकर केवल उन्हीं किसानों से सरकारी प्रकल्पों के लिए भूमि लेती है, जो स्वेच्छा से ऐसा करना चाहते हैं।

75. शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण और उन्नयन मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अभावग्रस्त क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, मेरी सरकार ने 1152 कॉलोनियां नियमित की हैं। इनमें से 601 कॉलोनियां शहरी स्थानीय विभाग द्वारा तथा 551 कॉलोनियां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा नियमित की गई हैं।

76. मेरी सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों की प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों को बढ़ाया है, बेहतर नियंत्रण और निगरानी के लिए निर्वाचित सदस्यों को सशक्त बनाया है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए राज्य वित्त आयोग अनुदान बजट को वित्त वर्ष 2022–23 के 2006 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 2574 करोड़ रुपये किया गया।

77. महानगरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला और हिसार में महानगर विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है।

78. माननीय सभासदो! उद्योग न केवल हमारी अर्थव्यवस्था का मूल आधार हैं बल्कि रोजगार–सृजन में भी इनकी अहम भूमिका है। मेरी सरकार ने उद्योग एवं व्यापार के अनुकूल परिवेश तैयार करने के लिए अनेक कारगर कदम उठाये हैं। इससे पूंजी निवेश के लिए आज हरियाणा देश–विदेश के उद्यमियों की पहली पसंद बन गया है।

79. इंटरैक्टिव पोर्टल के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों को एक ही स्थान पर मंजूरी प्रदान करने के लिए हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र स्थापित किया गया है। पोर्टल के माध्यम से अब 25 विभागों के 150 औद्योगिक अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। अब तक 3.67 लाख़ सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। हाल ही में राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के बीच राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना एक्सरसाइज एसेसमेंट में 'टॉप अचीवर' का दर्जा हासिल किया है।

80. इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति–2022 लागू की है। इस नीति में हरियाणा की वाहन निर्माण क्षेत्र में अंतर्निहित मजबूती का लाभ उठाकर ई–मोबिलिटी के लिए एक पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण पर विशेष बल दिया गया है। इसके अन्तर्गत 35 करोड़ रुपये की सब्सिडी जारी की गई है।

81. माननीय प्रधानमंत्री जी के 5 एफ विजन–'फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन' के अनुरूप हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल नीति 2022–2025 शुरू की गई, जिसका लक्ष्य 5000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करना और 3,00,000 लोगों को रोजगार देना है। दिसंबर 2023 में शुरू होने के बाद से, इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है।

82. मेरी सरकार विश्व बैंक और केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित 5 वर्षीय कार्यक्रम आर.ए.एम.पी. में सक्रिय रूप से भाग ले रही है, जिसका उद्देश्य केंद्र–राज्य संबंधों को सुधारना, एम.एस.एम.ई. की बाजार

और क्रेडिट तक पहुंच में सुधार करना और एस.एम.ई. को प्रोत्साहित करना है। राज्य सरकार द्वारा एक विस्तृत योजना तैयार की गई है और योजना के आधार पर 135.17 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

83. सफल कृषि–व्यवसाय और खाद्य प्रसंस्करण नीति–2018 और एम.एस.एम.ई.–2019 नीति को नया स्वरूप दिया जा रहा है और इन नीतियों के नए संस्करण तैयार किए गए हैं और वित्त वर्ष 2024–25 में अधिसूचित किए जाएंगे, जिनका लक्ष्य राज्य में 5000 करोड़ रुपये का निवेश और 30,000 लोगों को रोजगार देना है।

84. आज हरियाणा उद्योग के लिए एक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है और कुछ प्रमुख निर्माताओं ने राज्य में परियोजनाएं स्थापित की हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 800 एकड़ भूमि पर 18,000 करोड़ रुपये के निवेश और 20,000 व्यक्तियों के रोजगार के साथ आई.एम.टी. खरखौदा में एक कार निर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी आई.एम.टी. खरखौदा में 100 एकड़ क्षेत्र में 2000 करोड़ रुपये के निवेश और 2000 व्यक्तियों के रोजगार के साथ एक दोपहिया वाहन निर्माण सुविधा विकसित कर रही है।

85. राज्य में अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी, आई.एम.टी. सोहना और आई.एम.टी. खरखौदा में विकास कार्य शुरू कर दिए गए हैं। बेहतर औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मौजूदा विभिन्न औद्योगिक

क्षेत्रों में औद्योगिक बुनियादी ढांचे का उन्नयन कार्य चल रहा है। बड़ी और रोहतक में मेगा फूड पार्क भी क्रमशः 175 करोड़ रुपये और 180 करोड़ रुपये के निवेश के साथ विकसित किए जा रहे हैं।

86. अम्बाला और जींद में नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने तथा बावल, सोहना और खरखौदा के औद्योगिक मॉडल टाउनशिप के विस्तार के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत 10,800 एकड़ भूमि के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, राज्य के 23 स्थानों पर 30,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण भी ई–भूमि पोर्टल के माध्यम से पी.ए.डी.एम.ए. स्कीम के तहत विस्तार और नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए किया जा रहा है।

87. सरकार आई.टी./आई.टी.ई.एस., इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग (ई.एस.डी.एम.), मेडिकल उपकरण निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने, एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (ए.वी.जी.सी.), उभरती प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिक कचरा पुनर्चक्रण जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है और उपरोक्त क्षेत्रों के लिए समर्पित क्षेत्रीय नीतियां बनाई जा रही हैं।

88. हरियाणा मूल के अप्रवासी उद्योगपतियों और निवेशकों के समक्ष आ रही कठिनाइयों व शिकायतों का समाधान एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाने के लिए चंडीगढ़ में अप्रवासी भारतीय शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। हरियाणा उद्यम संवर्धन केंद्र के माध्यम से उद्यमों के लिए सिंगल रूफ क्लीयरेंस सिस्टम के तहत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सभी स्वीकृतियां जारी की जाती हैं।

पर्यावरण तथा संस्कृति संरक्षण

89. माननीय सभासदो! हमें न केवल आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पर्यावरण को संजोकर रखने की आवश्यकता है। मेरी सरकार ने प्रकृति की सुरक्षा के लिए यथासंभव कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने पराली को किसानों के लिए आय का साधन बनाने के साथ–साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए हरियाणा एक्स–सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी, 2023 अधिसूचित की है। यह नीति पराली–आधारित परियोजनाओं में निजी निवेश बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहन देकर पराली का उपयोग सुनिश्चित करने पर ध्यान केन्द्रित करेगी। इस नीति के तहत वर्ष 2027 तक फसल अवशेष जलाने की समस्या को खत्म करने का लक्ष्य है। किसानों को पराली का उचित मूल्य दिलाने के लिए मेरी सरकार ने कॉमन डिटरमाइंड प्राइस देने का निर्णय लिया है।

90. मेरी सरकार प्रदेश की विरासत, संस्कृति और पर्यटन को संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कुरुक्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई 97.34 करोड़ रुपये की राशि में से विभिन्न कार्यों के लिए 77.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। ज्योतिसर तीर्थ में 10 हजार वर्गमीटर क्षेत्र में 240 करोड़ रुपये की लागत से एक अति आधुनिक अनुभव केन्द्र का प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 16 फरवरी, 2024 को लोकार्पण किया है। इसमें महाभारत के दृश्यों को आधुनिक मल्टी मीडिया प्रणाली से दर्शाया गया है।

91. हैरिटेज सर्किट रेवाड़ी–महेन्द्रगढ़–माधोगढ़–नारनौल के अंतर्गत 29.61 करोड़ रुपये लागत की परियोजना पर कार्य शुरू हो चुका है। पंचकूला में नाडा साहिब गुरुद्वारा तथा श्री माता मनसा देवी मंदिर के विकास हेतु केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 47 करोड़ रुपये लागत की परियोजना पर कार्य जारी है। झज्जर में स्वामी ओमानंद सरस्वती संग्रहालय की स्थापना की एक परियोजना शुरू की गई है। हिसार के राखीगढ़ी में 6 एकड़ भूमि पर संग्रहालय एवं विवेचना केन्द्रों का निर्माण कार्य जारी है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के सम्मान में अम्बाला छावनी में 22 एकड़ क्षेत्र में शहीद स्मारक का निर्माण कार्य जल्द पूरा होने वाला है।

92. हमारे देश में समय–समय पर संत–महात्माओं, ऋषि–मुनियों, पीर–पैगम्बरों और गुरुओं ने समूची मानवता को जीवन का सच्चा रास्ता दिखाया है। ऐसी महान विभूतियों की शिक्षाएं पूरे समाज की धरोहर हैं। उनकी विरासत को सम्भालने व सहेजने की जिम्मेदारी हम सबकी है। मेरी सरकार ने आमजन, विशेषकर युवाओं को इनकी शिक्षाओं से अवगत करवाने के उद्देश्य से 'संत–महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना' शुरू की है।

कर्मचारी कल्याण

93. सरकारी कर्मचारी मेरी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में प्रशंसनीय भूमिका निभा रहे हैं। उनकी समस्याओं के निदान के लिए मेरी सरकार हमेशा तत्पर रहती है। सरकार ने कर्मचारियों को पदोन्नति के समान अवसर प्रदान करने के लिए ग्रुप–डी का कॉमन कैडर

बनाने का काम किया है। राज्य सरकार ने 01 जनवरी, 2024 से सभी कर्मचारियों के लिए व्यापक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा योजना शुरू लागू कर दी है। अब इस योजना का विस्तार राज्य के सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों तक कर दिया गया है। आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के तहत सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति के माध्यम से इलाज करवाने पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति का लाभ प्रदान किया जाएगा।

94. दिव्यांग महिला सरकारी कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए 1500 रुपये प्रति बच्चा विशेष भत्ता दिया जाता है। दस वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आंगनवाड़ी सहायक का मानदेय बढ़ाकर क्रमशः 14,000 रुपये, 12,500 रुपये तथा 7500 रुपये किया गया है। चौकीदारों का मानदेय बढ़ाकर 11,000 रुपये प्रतिमाह तथा वर्दी भत्ता 4000 रुपये प्रति वर्ष किया गया है। साइकिल भत्ता भी 3500 रुपये किया गया है। गांवों में कार्यरत सफाई कर्मियों का मानदेय 12,500 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये किया गया है। अब उन्हें समय पर मानदेय न मिलने पर 500 रुपये हर्जाना भी मिलेगा। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का सालाना वर्दी भत्ता 3500 रुपये से बढ़ाकर 4000 रुपये किया गया है।

95. मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत बोर्डों, निगमों और स्थानीय निकायों समेत सभी सरकारी कार्यरत ग्रुप–सी और डी के अनुबंध कर्मचारी की कार्यस्थल पर मृत्यु या दिव्यांग होने पर उन्हें या उनके परिजनों को 10 लाख रुपये

की सहायता राशि दी जाती है। सफाई कर्मचारी की मृत्यु या दिव्यांग होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।

96. सभी राजकीय अध्यापकों के लिए लागू 'ऑनलाइन स्थानांतरण नीति' का देश के अन्य राज्य भी अनुकरण कर रहे हैं।

97. हमें गर्व है कि हरियाणा के वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार ने युद्ध में शहीद हुए प्रतिरक्षा कर्मियों और केन्द्रीय सशस्त्र बलों के हरियाणा निवासी जवानों के परिवार के पात्र सदस्यों में से एक को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने के लिए 'अनुकंपा नियुक्ति नीति, 2023' तैयार की है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक सैन्य व अर्ध–सैनिक बलों के शहीद हुए कर्मियों के 369 आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है।

98. सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों व अर्द्ध–सैनिक बलों के कल्याण के लिए 'सैनिक व अर्ध–सैनिक कल्याण विभाग' का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों व केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की है। आई.ई.डी. ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपये तक की गई है। युद्ध, आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल/दिव्यांग हुए सैनिकों व केन्द्रीय अर्ध–सैनिक बलों के कर्मियों के लिए अनुग्रह अनुदान राशि निःशक्तता के आधार पर 15 लाख रुपये, 25 लाख रुपये तथा 35 लाख रुपये की गई है।

99. मेरी सरकार ने प्रदेश के 3 लाख से अधिक सभी अधिकारियों व कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों तथा सिद्धांतों का समावेश करने और उन्हें

प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से 'मिशन कर्मयोगी हरियाणा' के रूप में एक अभूतपूर्व पहल की है। इसके तहत अब तक 2,23,869 अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

100. प्रदेशवासियों ने अपने भविष्य को आकार देने और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का दायित्व मेरी सरकार को सौंपा था। उनके अपार स्नेह और विश्वास पर खरा उतरने की एक बड़ी चुनौती सरकार के समक्ष थी। परन्तु मुझे इस सम्मानित सदन को अवगत करवाते अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरी सरकार न केवल इस विश्वास पर खरी उतरी है अपितु उसने अपनी कार्य–शैली से आमजन में एक नया विश्वास जगाया है। प्रदेशवासियों का यही विश्वास मेरी सरकार का संबल है, जिससे हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।

101. मेरी सरकार क्षेत्र, जाति, धर्म और लिंग भेद की संकीर्ण भावना से ऊपर उठकर प्रदेश के हर वर्ग और हर व्यक्ति समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इस सम्मानित सदन में जीवंत और रचनात्मक परिचर्चाएं होंगी, जहां भिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को सुना जाएगा। आप सबका योगदान मेरी सरकार के लिए मार्गदर्शक का काम करेगा। आइए, हम एक उज्ज्वल और स्पंदनशील भविष्य के लिए मिलकर समृद्ध, समावेशी और प्रगतिशील हरियाणा बनाने के लिए कार्य करें।

वंदे मातरम!

जयहिन्द!

10873—C.S.—H.G.P., Pkl.